मेहनतकशों का पैग़ाम मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

पाक्षिक

Email : mazdoormorcha@yahoo.co.in
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06 /R.N.I. No. 66400/97

ई एस आई में बैठते हैं मज़दूर नेता केवल ऐय्याशी के लिये प्रशासनिक भ्रष्टाचार की आग लील गयी, लाखों की सम्पत्ति 3

अरविंद केजरीवाल और 'आप' विचारधाराहीन विकल्प 4

धार्मिक व मीडिया क्षेत्र का भ्रष्टाचार है कोई इनकी सुनने वाला? 6

अपराध–ग्राफ़ क्यों न बढ़े, जहां यह पुलिसिया आय से जुड़े 8

वर्ष 27 अंक 3 फरीदाबाद, सोमवार, 16-31 दिसंबर 2013 फोन : - 9999595632 ₹ 2

फ़िर जीते नेता, जनता कब जीतेगी ?

दिल्ली मज़दूर मोर्चा ब्यूरो

चार राज्यों–दिल्ली, राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ– में मतगणना की समाप्ति के साथ राजनीतिक प्राणियों/ पार्टियों का चुनावी दौर समाप्त हो गया। उम्मीदवारों/ पार्टियों में कोई हारा कोई जीता। जिस जनता ने इन चुनावों में मत डाले, क्या उनके लिये भी हार–जीत का परिणाम आ गया?

दरअसल जनता के लिये तो असली चुनाव अब शुरू होंगे। अगले चुनाव तक उसे हाथ पर हाथ धरे देखना है कि उसकी जीत हो रही है या हार। आज तक के सभी चुनाव हमें यही बताते आये हैं कि चुनावों के बाद जनता हमेशा हारती आयी है। और उसकी यह हार अगले 5 वर्ष तक या नये चुनावों तक बदस्तूर चलती रहती है।

मौजूदा चुनावों में व्यक्तिगत उम्मीदवारों के नज़रिये से देखें तो जीतने वाले दावा कर सकते हैं कि वे मतदाताओं को औरों की अपेक्षा अधिक स्वीकार्य हैं। राजनीतिक पार्टियों के नज़रिये से देखें तो जीतने वाले दलों का दावा होगा कि जनता ने उनकी नीतियों एवं कारगुज़ारियों में विश्वास व्यक्त किया है। इस लिहाज से देखा जाय तो लगेगा कि हर सीट और हर राज्य में मतदाता ही तो जीतता है। पर चुनावों के बाद मतदाताओं के साथ जो विश्वासघात होता आया है उस कहानी का निष्कर्ष ठीक इससे उलट है।

उम्मीदवार चुनने के राजनीतिक पार्टियों के अपने–अपने मापदंड होते हैं। पैसा, जाति, धर्म, वफ़ादारी, वोट–समीकरण के आधार पर ही प्राय: उम्मीदवार चुने जाते रहे हैं। इस बार दिल्ली के चुनाव में उतरी आम आदमी पार्टी (आप) ने मापदंड रखा कि उसके उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि आपराधिक और छवि बेइमान की न हो। अन्य पार्टियों ने तो पुरानी तर्ज पर ही बाहुबलियों, धंधेबाज़ों और विघटनकारियों से भी परहेज नहीं रखा। पर क्या 'आप' का भी मापदंड काफ़ी है? कांग्रेस भाजपा समेत तमाम अन्य सत्तारुढ़ रह चुकी पार्टियों के कितने उम्मीदवार मिल जायेंगे जो इस पैरामीटर पर खरे उतरेंगे। पर क्या ये चुने जाने पर जनता और देश को लूटने में किसी से पीछे पाये जाते हैं?

वर्षों सत्ता की मलाई डकारने वाली राजनीतिक पार्टियां पुराने वायदों को नई साज–सज्जा के साथ पेश करने में महारत पा चुकी हैं। मतदाताओं के पास उनके पाखंड को देखते रहने के सिवाय और कोई चारा भी नहीं रहता। मतदाता जानता है कि वह नागनाथ और सांपनाथ में से ही किसी को चुन रहा है

इस बार के चुनावों में 'आप' पार्टी ने एक अलग पहल दिखाई है। उन्होंने दिल्ली की हर सीट के लिये अलग–अलग घोषणापत्र जारी किये। उनका दावा रहा कि उनकी नीतियां और कार्यक्रम लोगों की सहभागिता से तय किये गये हैं। हालांकि इस तरह बने घोषणापत्रों में भी उन प्रणालियों का ज़िक्र नहीं किया गया है जिनसे जनता की आकांक्षायें पूरी की जायेंगी। उनके वायदों और अन्य पार्टियों द्वारा दिखाये सब्ज़बाग में इतना ही अंतर है कि पहली बार चुनाव में उतरने के चलते कोई 'आप' पर फ़िलहाल वायदाखिलाफ़ी का आरोप नहीं लगा सकता।

शेष पेज 2 पर

खेल, खिलाड़ी, खेल भावना पर भारी पड़ता खेल–प्रशासक

भारतीय ओलंपिक संघ और भारतीय मुक्केबाज़ी संघ दोनो केवल मात्र एक खेल–प्रशासक के निहित स्वार्थ के चलते निलम्बित चले आ रहे हैं। इन दोनों संघों को क्रमश:अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक संघ और अन्तर्राष्ट्रीय मुक्केबाज़ी संघ ने घोर अनियमितताओं के चलते निलम्बित किया हुआ है। दोनों संघ बदनाम अभय चौटाला के चंगुल में इस कदर फ़ंसे है कि उनका जल्दी उद्धार होना संभव नहीं लगता। अभय की इन पर पकड़ बढने का एक सबूत महीने भर पहले मिला जब भारत से एकमात्र अन्तर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के सदस्य रणधीर सिंह ने भी उसका समर्थन शुरू कर दिया। जबकि इससे पहले सैंकड़ों ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों के अभय–विरोधी हस्ताक्षर अभियान में वे अगुआ होते थे।

एक बार स्वाद चख लेने के बाद अभय की महत्वाकांक्षा बढती गयीं और अन्ततः उसने पैसे व दादागिरी के बल पर ऐन–केन प्रकारेण भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष का पद भी हथिया लिया। उधर मुक्केबाज़ी संघ के नियमानुसार क्योंकि वह लगातार तीसरी बार संघ का अध्यक्ष नहीं चुना जा सकता था, उसने वहां धींगामस्ती से स्वयं के लिये चेयरमैन का नया पद बनवा लिया।

वैसे तो भारतवर्ष में तमाम खेल संघों पर जो लोग काबिज़ हैं उनकी ताकत न खेल है, न खिलाड़ी और न ही खेल–भावना। उनकी पृष्ठभूमि या तो राजनीतिक है या व्यवसायिक या फ़िर अफ़सरशाही वाली। उनका लक्ष्य खेल या खिलाड़ी का विकास न होकर अपनी मौजमस्ती एवं चौधर में बढौतरी होता है। लाखों–करोड़ों का निवेश कर या रसूख का इस्तेमाल कर इन पदों को हथियाने के बाद ये खेल–प्रशासक कई गुणा ज़्यादा कमाई के चक्कर में लग जाते हैं। स्वाभाविक ही।

ऐसे माहौल में यदि बाहुबली किस्म वाले राजनीतिक जीव भी खेल की इस दुनिया की ओर आकृष्ट हों तो ताज्जुब क्या? कुश्ती में बाहुबली सांसद ब्रजभूषण सिंह और मुक्केबाज़ी में अपनी गुंडई के लिये बदनाम अभय चौटाला काफ़ी अर्से से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं। एक बार स्वाद चख लेने के बाद अभय की महत्वाकांक्षा बढती गयीं और अन्तत: उसने पैसे व दादागिरी के बल पर ऐन–केन प्रकारेण भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष का पद भी हथिया लिया। उधर मुक्केबाज़ी संघ के नियमानुसार क्योंकि वह लगातार तीसरी बार संघ का अध्यक्ष नहीं चुना जा सकता था, उसने वहां धींगामस्ती से स्वयं के लिये चेयरमैन का नया पद बनवा लिया।

शेष पेज 2 पर

ख़बर दार

5 करोड़ की अवमानना में अभिनेता राजपाल भुगत रहा सज़ा

22,000 करोड़ डकारनेवाला कार्पोरेट सुब्रत सहारा ले रहा मज़ा

फ़िल्म एवं टीवी के चर्चित हास्य–अभिनेता राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेशों की लगातार अवमानना से चिढ कर उसे 10 दिन के लिये तिहाड़ जेल भेज दिया। दूसरी तरफ़ सहारा श्री के नाम से स्वयं को देशभक्त नम्बर वन का खिताब देने वाला कार्पोरेट सुब्रत राय ने 22000 करोड़ डकार लिये हैं और वह इस मामले में लगातार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना कर रहा है। पर किसी में हिम्मत नहीं कि उसे जेल भेजना तो दूर, कुछ कह भी सके।

उल्टा, सुप्रीम कोर्ट के हर आदेश की अवमानना के बाद सुब्रत राय का सहारा ग्रुप कार्पोरेट मीडिया में बड़े–बड़े विज्ञापनों

के माध्यम से स्वयं को सही ठहराता है। राजपाल पर तो महज़ दिल्ली के एक व्यवसायी से धोखाधड़ी करने का आरोप है। जबकि सुब्रत ने 22 000 करोड़ की काली कमाई को, फ़र्ज़ी निवेशकों के नाम से दिखा कर, सफ़ेद किया हुआ है।

दोनों मामलों के तथ्यों पर सरसरी नज़र भी यह बता देगी कि राजपाल के मुकाबले सुब्रत का कुकृत्य हज़ारों गुणा बड़ा अपराध है। राजपाल ने केवल धोखा–धड़ी व वादा खिलाफ़ी की है पर सुब्रत राय का अपराध धोखाधड़ी एवं वादाखिलाफ़ी से कहीं आगे जाकर जालसाज़ी और देश–द्रोह का बनता है।

राजपाल ने अपनी फ़िल्म 'अता पता लापता' में एक व्यवसायी से 5 करोड़ का निवेश कराया था। अनुबन्ध के मुताबिक फ़िल्म की रिलीज़ और उसके संगीत से होने वाली आय में व्यवसायी का हिस्सा बनता था। पर राजपाल उसे टरकाता रहा।

शेष पेज 2 पर

दिल्ली चुनाव ने साबित कर दिया

दिल्ली चुनावों में जनता ने साबित कर दिया कि उसे भले–बुरे व ईमानदार–बेईमान की पहचान है। आम आदमी पार्टी (आप) ने साबित कर दिया कि राजनीति केवल लुटेरे, ठगों, अपराधियों तथा धन्ना–सेठों की बपौती नहीं है। चुनाव जीतने के लिये किसी बड़े राजनीतिक परिवार की छाप अथवा 'कद्दावर नेता' होना कतई जरूरी नहीं है; एक आम आदमी भी बिना पैसों के चुनाव जीत सकता है।

यह भी सिद्ध हो गया कि जनता को यदि बेहतर विकल्प मिले तो वह उसे अपनाती है। इस चुनाव में यदि 'आप' उपलब्ध न होती तो कांग्रेसी कुशासन से त्रस्त जनता भाजपा को ही विकल्प के रूप में अपनाने को मजबूर होती, यह जानते हुए भी कि यह भी कांग्रेस से कम भ्रष्ट नहीं है।

छत्तीसगढ व मध्यप्रदेश में भाजपा को जो जबरदस्त विजय मिली है वह न तो मोदी की वजह से मिली है और न ही वहां चल रही भाजपाई सरकारों की कार्यशैली से। वहां जो जीत मिली है वह केवल विकल्पहीनता की वजह से मिली है। भाजपा का विकल्प वहां केवल कांग्रेस ही था, जिसको सारे देश की जनता राष्ट्रीय स्तर पर भुगत ही रही है। राजस्थान में भी कांग्रेस का विकल्प केवल वही भाजपा नज़र आई जिसे 5 साल पहले जनता ने दुत्कारा था। यदि इन तीनों राज्यों में भी 'आप' अथवा ऐसा ही कोई विकल्प जनता के पास उपलब्ध होता तो भाजपा कदाचित इन राज्यों में जीत नहीं सकती थी।